

## घोटलों के मामले में कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं-हजारे

लखनऊ-समाजसेवी अग्रा हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की मंशा पर शक जाहिर करते हुए कहा है कि वित्तीय कदाचार के मामले में कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आये हजारे ने कहा, "केन्द्र सरकार ने लोकपाल कानून की धारा 44 में बदलाव करके उसे कमजोर कर दिया। एक तरफ तो मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करती हैं, दूसरी तरफ उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने वाले लोकपाल कानून को कमजोर कर दिया। खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग।"



उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्र सरकार की मंशा पर मुझे शक है। लोकपाल कानून की धारा 44 में प्रावधान था कि हर सरकारी अधिकारी अपने करीबी परिजन की सम्पत्ति का हर साल ब्यौरा देगा। मगर इसमें संशोधन करके उस अनिवार्यता को हटा दिया गया।" उन्होंने कहा कि केन्द्र की पिछली कांग्रेस और मौजूदा भाजपा सरकार में कोई अंतर नहीं दिखायी देता है। दोनों सत्ता और धन जुटाने में लित हैं। वे सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हैं। हजारे ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016 में लोकपाल कानून में संशोधन के विधेयक को बिना चर्चा कराये आनन-फानन में पारित कर दिया। उसने 27 जुलाई को लोकसभा और 28 जुलाई को राज्यसभा में इसे पारित करा दिया और 29 जुलाई को उस पर राष्ट्रपति ने भी दस्तखत कर दिये। यह तो कांग्रेस भी नहीं कर सकती थी। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बगैर कोई कानून बनाना लोकतंत्र नहीं, बल्कि 'हुक्मतंत्र' है।

वर्ष 2011 के आंदोलन के विपरीत इस बार

समर्थन जुटाने के लिए देश का दौरा करने संबंधी सवाल पर हजारे ने कहा "दोनों आंदोलनों के बीच में अंतराल ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। 96% चुनाव सुधारों को लेकर भी मुहिम चला रहे हजारे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की सपा और बसपा की मांग से असहमत जताती और कहा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में हम पीछे क्यों लौटें। हालाँकि, उन्होंने कहा कि ईवीएम की निष्पक्षता बनाये रखने के लिये 'टोटलाइजर मशीन' का इस्तेमाल किया जाये। ईवीएम को बदलने के बजाय तंत्र को बदला जाये।

हजारे ने इस बार अपने आंदोलन से जुड़ने वालों के लिये शर्त रखी है कि वे भाविष्य में कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने इस बारे में कहा, "गांधी जी कल्पना यह थी कि कोई भी आंदोलन चरित्र पर आधारित होना चाहिये। आज चरित्र पर कुछ भी आधारित नहीं है। हमें संख्यात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि गुणात्मक दृष्टि से आंदोलन को देखना चाहिये।"

### सऊदी अरब ने सैन्य अधिकारियों में किया फेरबदल

दुबई। यमन में लंबे खिंचते युद्ध के बीच सऊदी अरब ने रक्षा मंत्रालय में फेरबदल के उद्देश्य से सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों को आज उनके पदों से हटा दिया। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं की भूमिका में विस्तार करने के उद्देश्य से ग्राम एवं सामाजिक विकास की नई महिला उप मंत्री की नियुक्ति की भी घोषणा की। वाशिंगटन में सऊदी दूतावास में वरिष्ठ सलाहकार प्रिंस फैजल बिन फरहान ने ट्विटर पर लिखा, "यह पुनर्गठन कई वर्षों के प्रयास का हिस्सा है।" जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें सेना प्रमुख जनरल अब्दुलरहमान बिन सालेह अल बनयान शामिल हैं। एक अन्य घोषणा में कहा गया कि जनरल को शाही अदालत में सहलाकार बनाया गया है। अल बनयान की जगह जनरल फर्याद बिन हमिद अल रवैली ने ली है।

## सोहराबुद्दीन केस-रहूल ने न्यायाधीश के बदले जाने पर उठये सवाल



नई-दिल्ली-कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोहराबुद्दीन मामले में एक अन्य न्यायाधीश को बदले जाने पर सवाल उठाये। पूर्व में इसी मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश लोया की मौत हो गयी थी और उनकी मौत से जुड़ी याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है। राहुल ने आज ट्वीट कर कहा, "सोहराबुद्दीन मामले में एक और न्यायाधीश बदल गयी।" उन्होंने कहा, "न्यायमूर्ति रेवती को हटा दिया गया जिन्होंने सीबीआई को चुनौती दी। न्यायमूर्ति जे उत्पत ने अमित शाह से पेश होने के लिए कहा था और उन्हें हटा दिया गया।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "न्यायमूर्ति लोया ने कड़े शब्द पड़े थे। उनकी मौत हो गयी।" उन्होंने यह ट्वीट इस हैशटैग के साथ किया है, 'लोया की मौत कैसे हुई।' राहुल ने अपने इस ट्वीट के साथ एक वेबसाइट पर प्रकाशित खबर को टैग किया है जिसका शीर्षक है, "सोहराबुद्दीन शेख केस-ताजे सवाल क्योंकि मीडिया पर खबर प्रकाशन की रोक हटाने वाली और सीबीआई को आड़े हाथ लेने वाली न्यायाधीश को बदला गया।" यह मामला 12 साल से अधिक समय पहले गुजरात में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख की मौत से जुड़ा है।

### लंदन से लौटते ही पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को CBI ने किया गिरफ्तार

नई-दिल्ली-पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार्ति अभी लंदन से ही लौटे थे कि उन्हें सीबीआई ने चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। इसी मामले में कुछ दिन पहले ही उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कर रमन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन दिनों सीबीआई एस. भास्कर से पूछताछ कर रही है। सोमवार को ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एस. भास्कर ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

### विश्व की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत-मोदी



नई-दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशी निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया के साथ कारोबार करने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत-कोरिया कारोबार शिखर सम्मेलन में कहा कि सरकार ने कारोबार के लिए स्थिर माहौल बनाने की दिशा में काम किया है और मनामाने ढंग से फैसले लेने के चलन को खत्म किया है। मोदी ने कहा, "रोजाना के लेन-देन को सकारात्मक बनाना हमारा लक्ष्य है। हम संदेह को कुरेदने के बजाय भरोसे का विस्तार कर रहे हैं। यह सरकार की मानसिकता में संपूर्ण बदलाव दर्शाता है।" प्रधानमंत्री ने खरीद क्षमता के आधार पर भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "जल्द ही हम सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम आज विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी हैं। हम स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी पारिस्थितिकी वाले देशों में से भी एक हैं।" मोदी ने कहा कि सरकार नियमन और लाइसेंस की रूकावटें दूर करने की मुहिम पर है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि को तीन साल से बढ़ाकर 15 साल व इससे अधिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "अगर आप विश्व पर नजर दौड़ायें तो ऐसे बेहद कम देश हैं जहाँ अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण कारक एक साथ मौजूद हैं। ये कारक हैं लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और माँग। भारत में यह तीनों मौजूद है।" उन्होंने कोरियाई कारोबारियों से कहा कि भारत अब कारोबार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने उनके निवेश के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए हरसंभव उपाय का भी भरोसा दिया।

## श्रीदेवी निधन-शाहरुख खान और रजनीकांत पहुंचे अनिल कपूर के घर

मुंबई-अदाकारा श्रीदेवी के साथ काम कर चुके रजनीकांत, कमल हासन और शाहरुख खान जैसे सितारे उनके निधन पर संवेदना जताने कल रात उनके देवर एवं अभिनेता अनिल कपूर के घर पहुंचे। अदाकारा का पिछले सप्ताह अचानक दुबई में निधन हो गया था और उनका शव अभी तक भारत नहीं लाया गया है। अदाकारा की बेटी खुशी और ज़हबी रविवार से अनिल कपूर के घर पर हैं, जहाँ उनकी मौत की खबर के बाद से ही तमाम बॉलीवुड दिग्गज संवेदना व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। अनिल कपूर, श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के छोटे भाई हैं।

अनिल कपूर के जुड़ स्थित बंगले और श्रीदेवी के लोडेंडवाला निवास के बाहर उनकी आखिरी झलक पाने की उम्मीद में प्रशंसक बड़ी संख्या में एकत्रित हैं। कल रात शाहरुख खान अपनी पत्नी गीरी खान के साथ अनिल कपूर के घर पर पहुंचे। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'जोरो' में श्रीदेवी आखिरी

बार बड़े पदों पर नजर आएंगी। फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन भी कल अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने अनिल के घर पहुंचे।

रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के अलावा कपूर खानदान के करीबी एवं समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह भी वहां पहुंचे। बोनी कपूर की पहली पत्नी के बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए। इसके अलावा अनंत अंबानी, हर्षवर्धन कपूर, जावेद अख्तर और शबाना आज़मी, करिश्मा कपूर, इशान खट्टर, मनीष मल्होत्रा, अनुपम खेर, दिव्या दत्ता और सतीश कौशिक भी अनिल के घर पहुंचे।

बहरहाल, फिल्म 'चांदनी' की अदाकारा के शव को भारत कब लाया जाएगा यह अभी साफ नहीं है। दुबई पुलिस के बयान और भारतीय मीडिया की तमाम अटकलों के बीच संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने कल शाम ट्वीट किया कि

यह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दो-तीन दिन का समय लगता ही है। सूरी ने लिखा, 'श्रीदेवी के निधन की खबर में मीडिया की रुचि को समझा जा सकता है लेकिन बेकार की अटकलों का कोई फायदा नहीं है। इस पर ध्यान दें कि पहला, हम उनका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं।'

उन्होंने लिखा, 'दूसरा, हम श्रीदेवी के परिवार और चाहने वालों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम उनका दर्द समझते हैं। तीसरा, ऐसी मामलों में हमारे अनुभव से हमें पता है कि प्रक्रिया पूरी होने में दो से तीन का समय लगता है। चौथा, विशेषज्ञों को उनके निधन के कारणों का पता लगाने दें। जिम्मेदार बनें।' दुबई सरकार ने कल कहा था कि मामला "दुबई सार्वजनिक अभियोजन" को सौंप दिया गया है, जिसमें ऐसे मामलों में अपनायी जाने वाली कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।